



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239 ]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1, 2001/भाद्र 10, 1923

No. 239]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1, 2001/BHADRA 10, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2001

**विषय:- चीन जनवादी गणराज्य मूल के या वहाँ से निर्यात किए गए डाइक्लोफेनाक सोडियम के भारत में आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच शुरू करना ।**

सं. 44/1/2001-डीजीएडी.— मैसर्स आरती ड्रग्स लि., अमोली आर्गेनिक्स लि. और कैरव कैमिकल्स लि. ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहाँ से निर्यातित डाइक्लोफेनाक सोडियम के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जाँच करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

## 2. विचाराधीन उत्पाद:

वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद डाइक्लोफेनाक सोडियम हैं । इस का प्रयोग ज्वलनरोधी एवं पीड़नाशक दवा के रूप में किया जाता है



याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सभी प्रकार के डाइक्लोफेनाक सोडियम को अध्याय शीर्ष 29.42 में वर्गीकृत किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि जिस वर्गीकरण के अन्तर्गत इनका आयात किया गया है उसकी अनदेखी करते हुए विचाराधीन उत्पाद के खिलाफ जाँच शुरू की जानी चाहिए। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह मौजूदा जाँच के दायरे पर किसी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

### 3. घरेलू उद्योग

यह याचिका मै0 आरती ड्रग्स लि., अमोली आर्गेनिक्स लि. और कैरव कैमिकल्स लि0 द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि वे कुल भारतीय उत्पादन के अधिकांश हिस्से को उत्पादन करते हैं। याचिकाकर्ता प्रथम दृष्ट्या उपरोक्त नियमों के नियम 5(3)(क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के आधार का मापदंड पूरा करते हैं।

### 4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है।

### 5. समान वस्तु

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित माल, संबद्ध देश के मूल के या वहाँ से निर्यातित माल के समान वस्तु है। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजन से याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित माल को उपरोक्त नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

### 6. सामान्य मूल्य

सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के अनुबंध-1 में दिनांक 15.7.99 की अधिसूचना सं0 44/99-सी. शु. (एनटी द्वारा और बाद में दिनांक 31 मई, 2001 की अधिसूचना सं0 28/2001 (एनटी) द्वारा संशोधन कर उसमें निम्नलिखित सिद्धांत 7 शामिल किया गया था:



गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित लागत के आधार पर अथवा किसी ऐसे तीसरे देश से रत समेत अन्य देशों के लिए कीमत के आधार पर किया जाएगा अथवा जहाँ यह संभव न हो वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित लाभ मार्जिन यदि आवश्यक हो, को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन करके समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत समेत किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन संबद्ध देश के विकास स्तर और संदर्भाधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए, उचित ढंग से किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का विधिवत ध्यान रखा जाएगा । जहाँ उचित हो वहाँ किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में यदि कोई जांच की गई हो तो उसकी समय-सीमा का ध्यान भी रखा जाएगा । जांच संबंधी पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपरोक्त चयन की सूचना अविलम्ब दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समयावधि प्रदान की जाएगी ।

इन नियमों में दिनांक 31.5.2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 28/2001(एनटी) द्वारा आगे और संशोधन किया गया है जिसके द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत 8 सम्मिलित किया गया है और इसकी टिप्पणी में चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है ।

"इस पैराग्राफ की टिप्पणी के अनुसार "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" शब्द से तात्पर्य ऐसे प्रत्येक देश से है जो उक्त टिप्पणी में सूचीबद्ध है और इसमें ऐसा कोई भी देश शामिल है जिसका निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्धारण करते हैं और जो देश लागत और कीमत निर्धारण संबंधी ढांचे के बाजार सिद्धांतों पर कार्य नहीं करता है जिससे कि ऐसे देश में वस्तुओं की बिक्री से उक्त वस्तु के उचित मूल्य का पता चल सके । ऐसा निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करेगा कि क्या,

- (i) कच्ची सामग्रियों समेत कीमतों, लागतों और निविष्टियों, प्रौद्योगिकी एवं श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियों एवं निवेश के बारे में ऐसे देश की संबंधित फर्मों का निर्णय आपूर्ति एवं



मांग को प्रदर्शित करने वाले बाजारी संकेतों के अनुरूप और इस बारे में महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप के बिना लिया जाता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत से बाजार मूल्य पर्याप्ततः प्रदर्शित होते हैं;

- (ii) ऐसीस फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन है जो पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली, खासकर पारिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास, अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनियम व्यापार और ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के कारण आई हैं
- (iii) ऐसी फर्में दिवालियापन और सम्पत्ति संबंधी ऐसे कानूनों के अधीन हैं जो फर्म के प्रचालन हेतु कानूनी निश्चितता और स्थायित्व की गारंटी प्रदान करते हैं; और
- (iv) विनियम दर परिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है

किन्तु रूस और चीन जनवादी गणराज्य की बदलती हुई आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट करकों के बारे में लिखित में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रदर्शित किया जाता है कि ऐसी ही एक अथवा अधिक फर्मों के लिए विद्यमान बाजारी दशाएं पाटनरोधी जांच के अधीन हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के बजाय पैराग्राफ 1 से 6 तक (उक्त नियमों के अनुबंध-1) में निर्धारित सिद्धांतों का प्रयोग कर सकता है।

### टिप्पणी

इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल हैं अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलरूस, चीन जनवादी गणराज्य, जार्जिया, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, रूस ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उक्रेन, उजबेकिस्तान एवं विएतनाम। इनमें से ऐसा कोई देश जो यह प्रमाणित करना चाहता है कि वह इस पैराग्राफ में वर्णित मापदंड के अनुसार एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है तो वह सभी आवश्यक सूचना प्रदान कर सकता है जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूरा ध्यान दिया जाएगा।

उपरोक्त यथासंशोधित नियमों के अनुसार, याचिकाकर्त्ताओं ने चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का दावा भारत में संबद्ध वस्तुओं के परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर किया है।



उपरोक्त नियमों के अनुसार यदि चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातक अपने निर्यातों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से होने का दावा करते हैं तो उसके लिए उपरोक्त नियमों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करना अनिवार्य होगा ।

प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के लिए उसे प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में मान लिया है ।

## 7. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ताओं ने भारत में किए गए वास्तविक आयात के आधार पर संबद्ध देशों से निर्यात कीमत का दावा किया है । कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, ऋण लागत, निर्यातकर्ता देश में अन्तर्राज्यीय परिवहन, बंदरगाह पर हैंडलिंग और पतन प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है ।

## 8. पाटन मार्जिन

इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जिससे इस बात का प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि निर्यातकों द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

## 9. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंड जैसे बिक्री प्राप्ति में गिरावट, लाभप्रदता में गिरावट, कीमत में कटौती, कम क्षमता उपयोग, संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि समग्र तथा संचयी रूप से प्रथम दृष्टया यह बताते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति होने का खतरा है ।

## 10. पाटनरोधी जांच का आरंभ

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं ।



**11. जांच की अवधि**

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 जनवरी 2001 से 31 अगस्त 2001 तक की है ।

**12 सूचना देना:**

संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत में इस जाँच से जुड़े ज्ञात संबद्ध आयातकों को संबंधित सूचना निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से देने और अपने विचार निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजने के लिए अलग से लिखा जा रहा है ।

**13. समय-सीमा**

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उनका अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

**14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

नियम 6(7) के अनुसार रूचि रखने वाली कोई भी पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश दिए गए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना देने से मना करती है या उचित समय के भीतर अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जाँच में बाधा डालती हैं तो प्राधिकारी, अपन पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार का यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

एल. बी. सप्तर्षि, निर्दिष्ट प्राधिकारी



**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st September, 2001

**Sub:- Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports into India of Diclofenac Sodium originating in or exported from China PR.**

**No. 44/1/2001-DGAD-** M/s Aarti Drugs Limited., Amoli Organics Limited and Kairav Chemicals Ltd., have filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Diclofenac Sodium originating in or exported from Peoples' Republic of China (hereinafter referred to as subject country) and requested for initiation of Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

2. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION:**

The product under consideration in the present petition is Diclofenac Sodium. This is used as anti inflammatory and analgesic drug. Petitioners have claimed that all types of Diclofenac Sodium are classified in chapter heading 2942. Petitioners have requested that the investigations be initiated against the product under consideration irrespective of the classification under which they are imported. Customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

3. **DOMESTIC INDUSTRY**

The petition has been filed by M/s Aarti Drugs Limited., Amoli Organics Limited and Kairav Chemicals Ltd.. The petitioners have claimed that they account for a major proportion of the total Indian production. Prima facie the petitioners satisfy the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.

4. **COUNTRY INVOLVED:**

The country involved in the present investigation is the China PR.

5. **LIKE ARTICLE:**

The petitioners have claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from subject country. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as



‘like articles’ of the product imported from the subject country within the meaning of the Rules supra.

6. **NORMAL VALUE:**

Annexure 1 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 had been amended vide Notification No. 44/99-CUS(NT), dated 15-7-99 and subsequently Notification No. 28/2001(N.T.) dated 31<sup>st</sup> May, 2001 whereby the following Principle 7 had been added:-

**“In case of imports from non-market economy country, Normal Value shall be determined on the basis of the price of constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the Designated Authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”**

Vide Custom Notification No.28/2001(NT) dated 31.5.2001, further Principle 8 as under has also been inserted and in the Note appended thereto Peoples’ Republic of China has been included in the list of non-market economy country:

**“The term “non market economy country” subject to the Note to this paragraph means every country listed in the note and includes any country which the Designated Authority determines and which does not operate on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise. While making such determination, the Designated Authority shall consider as to whether,**

- (i) the decision of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in respect to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether cost of major inputs substantially reflect market values;**
- (ii) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write offs, barter trade and payment via compensation of debts;**



- (iii) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and
- (iv) the exchange rate conversions are carried out at the market rate;

Provided that in view of the changing economic conditions in Russia and in the Peoples' Republic of China, where it is shown on the basis of sufficient evidence in writing on the factors specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms are subject to anti-dumping investigations, the Designated Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 ( of Annexure 1 of Rules supra) instead of the principles set out in this paragraph.

**Note:** For the purpose of this paragraph, the list of non-market economy country is Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Peoples' Republic of China, Georgia, Kazakstan, North Korea, Kyrgyzstan, Mongolia, Russia, Tajikstan, Turkmeistan, Ukraine, Uzbekistan and Vietnam. Any country among them seeking to establish that it is a market economy country as per criteria enunciated in this paragraph, may provide all necessary information which shall be taken due account by the Designated Authority."

In accordance to the Rules as amended above, the petitioners have claimed Normal Value for China PR on the basis of Constructed Normal Value of the subject goods.

In terms of the aforesaid Rules it will be incumbent upon the exporters from the China PR, in case they claim their exports to be from market economy country, to provide sufficient evidence to the Designated Authority in accordance with the aforesaid Rules.

The Authority has considered the same as prima facie evidence for Normal Value.

#### 7. EXPORT PRICE:

The petitioners have claimed the export price from the subject country based on the information about actual imports made in India. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, credit cost, inland transportation in the country of exports, port handling and port charges to arrive at the Export Price at ex-factory level

#### 8. DUMPING MARGIN

There is prima facie evidence that Normal Value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price indicating prima facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject country.

#### 9. INJURY AND CAUSAL LINK

Various parameters relating to injury such as the decline in the sales realisation, price undercutting, decline in profitability, price suppression, underutilisation of capacity, increase in rate of growth of imports from subject country, prima facie indicate collectively and cumulatively that there is threat of material injury to the domestic industry on account of dumping.



**10. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS**

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

**11. PERIOD OF INVESTIGATION**

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st January, 2001 to 31<sup>st</sup> August, 2001.

**12. SUBMISSION OF INFORMATION**

The exporters in the subject country and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi – 11 00 11.

**13. TIME LIMIT**

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

**14. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interest party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority